भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2927
13.08.2026 को उत्तर के लिए

सीसीपीआई में रैंकिंग

2927. श्री गोला बाबूराव :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक (सीसीपीआई) में 10वें स्थान से गिरकर 23वें स्थान पर पहुँचने को किस दृष्टि से देखती है;
(ख) भारत के 2024 तक लगातार छह वर्षों तक शीर्ष 10 उच्च-निष्पादन वाले देशों में शामिल रहने और 2015 से 2023 के बीच कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 14 प्रतिशत तक ले जाने की उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, इस प्रकार की तीव्र गिरावट के क्या कारण हैं;
(ग) उन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत सीसीपीआई द्वारा निष्पादन दर्शाया गया है;
(घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनज़र प्रस्तावित कार्य-योजना क्या है; और
(ङ) नए कोयला विद्युत संयंत्रों के संचालन को कम करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) 2026 में भारत की स्थिति 23वें स्थान पर बताई गई है। सीसीपीआई एक आकलन है जो जर्मनी में स्थित गैर सरकारी संगठनों जर्मनवॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (सीएएन) इंटरनेशनल द्वारा वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है। सरकार नीति निर्माण के आधार के रूप में ऐसी बाहरी रैंकिंग को मान्यता नहीं देती है, क्योंकि भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्राथमिकताओं और विकासात्मक जरूरतों द्वारा निर्देशित होती है।

वार्षिक सीसीपीआई रैंकिंग में भिन्नता इसकी अपनी कार्यप्रणाली और मापदंडों को दिए गए वेटेज और सूचकांक द्वारा अपनाए गए सापेक्ष स्कोरिंग फ्रेमवर्क पर आधारित होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार, भारत स्वच्छ ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जो स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (बड़े जलविद्युत को छोड़कर) मार्च 2014 में 4.1 गीगावाट से बढ़कर दिनांक 30.06.2026 तक 236.52 गीगावाट हो गई, अर्थात इसमें 57.69 गुना की बढ़ोतरी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2014-15 में 190.96 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 477.79 बीयू (कुल बिजली उत्पादन का 25.97%) हो गया है।

(ग) सीसीपीआई कई गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग करके निम्नलिखित चार श्रेणियों के तहत देशों का मूल्यांकन करता हैः-

1. ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन:
2. नवीकरणीय ऊर्जा:
3. ऊर्जा उपयोग; और
4. जलवायु नीति।

(घ) सरकार समानता और 'साझा परंतु भिन्न-भिन्न ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों का पालन करते हुए, राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास की प्राथमिकताओं और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर संधारणीय विकास और जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने जलवायु संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों और योजनाओं के तहत कई दूरदर्शी उपायों की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन;
- पीएटी (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार) और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के तहत प्रमुख क्षेत्रों के लिए अधिसूचित चरणबद्ध रूप से परिवर्तन कार्य योजनाएं
- राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन का निरंतर कार्यान्वयन है:
- वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन (एनईएम)
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीटीएस) के तहत भारतीय कार्बन बाजार का प्रचालन;
- केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में पांच वर्षों के लिए ₹20,000 करोड़ के आवंटन के साथ कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) को बढ़ावा देना;
- अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सहयोग, प्रौद्योगिकी अंतरण और जलवायु वित्त को सुविधाजनक बनाने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 का लाभ उठाना;
- राज्य स्तर पर जलवायु कार्रवाई योजनाएं; और
- संधारणीय खपत को बढ़ावा देने के लिए लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के अंतर्गत पहलें।

ये कार्य भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की प्रति इकाई आर्थिक उत्पादन पर होने वाले उत्सर्जन को 47% तक कम करना; गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 60% प्राप्त करना; और वर्ष 2035 तक वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र को बढ़ाकर 3.5-4.0 बिलियन टन सीओ2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए अद्यतन किया गया है।

पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर -1) के अनुसार, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई आर्थिक उत्पादन पर होने वाले उत्सर्जन में 37.38% की कमी (वर्ष 2005-2022) प्राप्त कर ली है, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 53.75% बिजली उत्पादन क्षमता (दिनांक 31.05.2026 तक की स्थिति के अनुसार) प्राप्त कर ली है, और वर्ष 2022 में 2.44 बिलियन टन सीओ2 के बराबर कार्बन सिंक बनाया है। भारत ने यूएनएफ़सीसीसी को अपनी 'दीर्घकालिक कम-उत्सर्जन विकास रणनीति' (एलटी-एलईडीएस) भी

सौंपी है, जिसमें वर्ष 2070 तक 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन का लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया गया है।

इसके अलावा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा की उपयोग का विस्तार करना, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना और अपनी लंबी अवधि की जलवायु और स्वच्छ-ऊर्जा रणनीति के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर ऊर्जा-दक्षता के उपायों को लागू करना जारी रखता है।

(ङ) भारत सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांत के अनुसार और 'चरणबद्ध कटौती' के माध्यम को अपनाते हुए, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने जीवाश्म ईंधन भंडार का उपयोग करना जारी रखेगा । भारत की बिजली की मांग कोयला, गैस, जलविद्युत, सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा सहित विविध ऊर्जा मिश्रण के माध्यम से पूरी की जाती है। दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 548.9 गीगावाट थी, जिसमें 251.5 गीगावाट थर्मल, 8.8 गीगावाट परमाणु और 288.6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों- हाइड्रो, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा) से प्राप्त क्षमता शामिल थी।

सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से क्षमता वृद्धि को प्राथमिकता दे रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत ने 44.6 गीगावाट सौर और 6.1 गीगावाट हवा के साथ कुल 55.3 गीगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाई, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति को दर्शाती है।

चूंकि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत आंतरायिक हैं, इसलिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र विश्वसनीय बेस लोड बिजली प्रदान करना और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, विशेष रूप से पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुमानों के आधार पर, पीएसपी की कुल स्थापित क्षमता वर्ष 2033-34 तक 87 गीगावाट तक पहुंचने और 2035.36 तक 100 गीगावाट को पार करने की उम्मीद है।

सरकार दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत के परिवर्तन के एक प्रमुख घटक के रूप में परमाणु ऊर्जा का भी विस्तार कर रही है। केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 में वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, 8.78 गीगावाट परमाणु क्षमता चालू है, 8.0 गीगावाट निर्माणाधीन है और वर्ष 2021-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है और 5.6 गीगावाट परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

- एक विविध उत्पादन स्रोतों का मिश्रण।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार
- विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कोयला आधारित क्षमता
- दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति के एक भाग के रूप में परमाणु क्षमता संवर्धन पर बल।

****